गुजरात शहरी विकास परियोजना

1136. **श्री गोपाल सिंह जी0 सरेलंकी** : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)क्या गुजरात सरकार ने राज्य के महत्वपूर्णए कस्बों के विकास हेतु विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने के लिए "गुजरात शहरी विकास परियोजना" तैयार की हैं;

(ख)यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग)क्या गुजरात सरकार ने राज्य के गंदी बस्तियों वाले कस्बों में सुविधाओं के विकास एवं सुधार के लिए ओ0डी0ए0 ब्रिटेन, से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु कोई अन्य परियोजना भी तैयार की हैं; और

(घ)यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में शहरी विकास विभाग के राज्य मंत्री (**श्री आर0 के0 धवन**) : (क) और (ख) विश्व बैंक सहायता प्राप्त गुजरात शहरी विकास परियोजना –। गुजरात में चल रही थी। परियोजना मार्च, 1995 में बन्द हो गयी।

गुजरात सरकार ने विश्व बैंक सहायता हेतु 794 करोड़ रू0 की अनुमानित लागत की भावी गुजरात शहरी विकास परियोजना-ii नामक दूसरा प्रस्ताव जनवरी, 1994 में भारत सरकार को भेजा। परियोजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं:-

1.शहरी जल आपूर्त्ति दूषित जल निकासी और बरसाती पानी के निकास में गम्भीर न्यूताओं को कम करना।

2. जल आपूर्त्ति सीवरेज और स्वच्छता के तह शामिल किये जाने वाले क्षेत्र के दायरे को बढ़ाना।

3.पूरी 100% स्लम आबादी को जल आपूर्त्ति, सीवरेज और स्वच्छता तथा सस्ती सफाई दायरे में लाना।

4.अधिक से अधिक शहरी गरीबों को उपर्युक्त कथित सेवाओं के दायरे में लाना।

5.स्वास्थ्य खतरे कम करना, समग्र लोक स्वास्थ्य में सुधार करना तथा नागरिकों को सुख पहुंचाना।

6.लाभर्थियों से पूरी लागत वसूली आरम्भ करना,

7.स्थानीय निकायों/शासन के दायरे में इंजीनियरी कार्यों बावत प्रशासन नियोजन, वित्त प्रबंध समग्रए कार्य कुशलता मजबूत करना।

भारत सरकार द्वारा परियोजना की जांच की गयी और आवश्यक कार्रवाई हेतु कुछ टिप्पणियां गुजरात सरकार को भेजी गयीं। इस बीच, विश्व बैंकए ने सूचना दी कि वे बैंक स्तर पर त्रण देने की पूर्व प्रक्रिया को बदल की प्रोजेक्ट को उधार देने की बजाए वित्तीय बिचौलियोंए की मार्फत कर्ज देने पर पुन: विचार कर रहे हैं। बिचौलिया बाबत दृष्टिकोण पर विश्व बैंक ने अपना अंतिमए निर्णय सूचित नहीं किया हैं।विश्व बैंक के निर्णय के आधार पर गुजरातण सहित सभी राज्यों को विश्व बैंक मदद वाली परियोजना तैयार करके वित्तीय बिचौलियों को दिखाने का नया रास्ता अपनाना होगा।

(ग) और (घ) 50,000 परिवारों वाले 336 स्लमों के उन्नयन हेतु "बडौदा-2000" नामक एक परियोजना प्रस्ताव गुजरात सरकार द्वारा तैयार किया गया और वह नवम्बर् 1992 में भारत सरकार को भेजा गया। प्रस्ताव इंगलैंड (यू0के) के ओवरसीज डेववलपमेंट एडमिनिस्टरेशन (ओ0डी0ए0) को (विचारार्थ (भेजा गया था, (ओ0डी0ए0) के पर्यवेक्षक दल ने जुलाइ, 1994 में प्रस्तावित परियोजना स्थल का दौरा किया।ए तब एक प्रायोगिक स्लम सुधार परियोजना तैयार की गयी और ओ0डी0ए0 के विचारार्थ रखी गयी हैं। इस बारे में ओ0डी0ए0 को अभी निर्णय लेना हैं।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गोंए के लिए "हुडको" से धनराशियां आबंटित करने हेतु मध्य प्रदेश का प्रस्ताव

1137. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को ऐसा प्रस्ताव प्रेषित किया हैं जिसमें यह अनुरोध किया गया हैं कि चालू वर्ष के दौरान राज्य के शहरी, ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए "हुडको" से धन आवंटित किया जाये;

(ख)यदि हां, तो तत्संबंधी जिलावार ब्यौरा क्या हैं;

(ग)सरकार की इस पर क्या प्रतिकिया हैं; और

(घ)इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एस0 एस0 अहलुवालिया) 3 (क) से (घ) राज्य सरकारों की एजेंसियों द्वारा तैयार आवास स्कीमें मूल्यांकन और स्वीकृति हेतु सीधे ही हुडको में प्राप्त होती हैं।

1995-96 के दौरान (31.10.95 तक) हुडको ने मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिएए निम्नलिखित दो स्कीमें स्वीकृत की हैं:-

	जिले का नाम	ऋण राशि (रूपये लाखों में)
1.	जबलपुर	27.00
2.	जबलपुर	16.50
	योग:	43.50

इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में शहरी /ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए निम्नलिखित चार स्कीमों पर हुडको विचार कर रहा हैं:-

	जिला	ऋण राशि (लाख रूपये में)
1.	शिपुर	39.00 (शहरी)
2.	भोपाल	03.60 (शहरी)
3.	शाजपुर	16.05 (शहरी)
4.	रायगढ़	16.24 (ग्रामीण
	योग:	74.89

इन स्कीमोंए की स्वीकृति ऋण लेने वाली एजेंसियों द्वारा हुडको दिशा-निर्देशों के तहत यथा अपेक्षित विभिन्न औपचारिकताएं पूरा करने पर निर्भर होगी।

Expansion Programme for Atomic Power Plants

1138. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government and the Nuclear Power Corporation Programme to have expansion programme of Atomic Power Plants;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government propose to have assistance from foreign countries for the expansion programmes of Atomic Power Plants; and

(d) if so, the details in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI):

(a) and (b) The Nuclear Power Profile drawn up by the Department of Atomic Energy envisages setting up a number of nuclear power plants of 220 MWe and 500 MWe capacity for enhancing the installed nuclear power capacity. However, actual implementation of these projects is being done depending upon the availability of resources.

(c) and (d) Yes, Sir: Feasibility of setting up 2x1000 MWe nuclear power station at Kudankulam with Russian assistance is being explored.

Intensive Survey of Rail Track in Andhra Pradesh

1139. SHRI YERRA NARAYANA-SWAMY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to conduct an intensive survey of rail track in Andhra Pradesh to identify weak and vulnerable spots;

(b) if so, by when this programme would be undertaken;

(c) whether any effort has been made in this direction in 1995-96 in Andhra Pradesh; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE